भारत के उपराष्ट्रपति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा 10 नवम्बर, 2007 को 11 बजे रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया अभिभाषण

10 नवम्बर, 2007
नई दिल्ली।

देवियो और सज्जनो,

मैं रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहां आपके बीच होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी इसके एक सदस्य के रूप में समारोह में हिस्सा ले रहा हूँ। आई डी एस ए ने इन वर्षों में सामरिक मामलों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने लिए एक स्थान बनाया है। इन कार्यों ने कुछ हद तक अवधारणा बनाने, और उन्हें जरूरी भारतीय आयाम देने में योगदान दिया है।

दर्शनशास्त्री, रेने डेसकार्ट्स ने कहा था कि 'मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ', इस तर्क से सोचना एक सामान्य और सार्वभौमिक मानवीय प्रवृत्ति है तथापि, अनुभव से पता चलता है कि व्यवस्थित सोच से बचने और इसे सामाजिक या संगठनात्मक पदानुक्रम में या तो किसी वरिष्ठ के लिए छोड़ने या तो किसी छोटे समूह को ऐसा करने का आदेश देने की प्रवृत्ति होती है। दोनों ही मामलों में यह नागरिक उत्तरदायित्व का परित्याग है जैसे कि पेरिक्लीज ने बहुत पहले कहा था कि सामान्य नागरिक सार्वजनिक मामलों के निष्पक्ष निर्णायक होते हैं और इसलिए 'बहस किसी बुद्धिमत्ता-पूर्ण कार्य के लिए अवरोधक नहीं अपितु एक अपरिहार्य पूर्व व्यवस्था' होती है।

परिदृश्य के दूसरी ओर तत्समय के झमेलों में व्यस्त सरकारों के पास कभी कभी व्यवहार्य, संभावित और यहां तक कि असंभावित चीजों पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए फुर्सत और ऊर्जा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में काल्पनिक परन्तु ठोस सोच अपनी प्रासंगिकता दिखाती है और विचारों एवं कार्य की दुनिया के बीच के अंतर को दूर करने में सहायता करती है।

समाजशास्त्री अंथोनी गिडन्स, जो हाल ही में दिल्ली में थे, ने आज की दुनिया को "उलझनपूर्ण, विचित्र, अपरिमित" बताया है जिसमें 'हम उन शक्तियों को नियंत्रित करने से काफी दूर हैं जिन्हें हमने मुक्त किया है।' यह और भी जटिल स्थिति हो गई है जैसे कि फिलिप बोबिट ने कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित एक मौलिक पुस्तक में लिखा है कि 'यह स्थिति राष्ट्र राज्य से बाजार-राज्य में वैधता के आधार परिवर्तन' से आई है जो सार्वभौमिकता के सिद्धान्त पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसलिए सुरक्षा और विदेश नीति की दृष्टि से आज के विश्व के बारे में सोचने के लिए नई चीजों की जानकारी की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ स्पष्ट हैं और निम्नलिखित रूप में उल्लिखित किए जा सकते हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति और फुटकर स्तर पर प्रयोक्ता अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उद्‌भव हुआ है जिससे व्यक्तिगत स्तर पर व्यापक सशक्तीकरण हुआ है।
- बाजारी एकीकरण और त्वरित संचार मीडिया के साथ भूमंडलीकरण ने ग्राम स्तर पर व्यापक अंतनिर्भरताएं सृजित की हैं।
- शीत युद्ध की समाप्ति और अधिक जटिल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उद्‌भव से घिसे पिटे रूप की ओर बहुत कम झुकाव है। संबद्धता, गठबंधन और पहचान अब अलग नहीं रहे- व्यपगत बहुलता अब न केवल एक विकल्प रह गयी है, यह एक आवश्यकता बन गई है।
- 'शक्ति' और 'प्रभाव' की अवधारणा में अत्यधिक बदलाव आया है। आज सुदृढ़ माने जाने वाले राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों से अधिक संशंकित हैं। गैर सरकारी क्षेत्र की ताकतें प्रौद्योगिकी रूप से इतनी सशक्त हो गई हैं कि वे राज्यों और समाजों के बीच व्यापक विनाश कर सकती हैं। नरम शक्ति प्रदर्शन उग्र शक्ति प्रयोग की तरह महत्वपूर्ण है।
- राष्ट्रों का राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक डी एन ए लोगों के विकास और समृद्धि हेतु विद्यमान क्षमता की सीमा के रूप में कार्य करता है। लोगों की ऊर्जा के दोहन के लिए इस क्षमता का कार्यान्वयन हमेशा उस समय के राजनैतिक और सामाजिक वातावरण और मौजूदा नेतृत्व पर निर्भर करता है।

- मौलिक मानवाधिकारों पर व्यापक ध्यान गया है तथा उसे मानव इतिहास में मान्यता मिली है। वे राष्ट्रों के लिए स्पष्ट और निहित व्यवहार कोड अधिरोपित करते हैं, चाहे राष्ट्रीय संविधान और घरेलू कानून कैसे भी हों।
- हमारी जनसंख्या के मुख्यत: युवा वर्ग के 550 मिलियन भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं- सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य हस्तक्षेपों और सुविधाओं के संबंध में धैर्य क्षीण हो रहा है। लोग आय में वृद्धि चाहते हैं, जीवन स्तर ऊंचा चाहते हैं और शीघ्र अपनी संभाव्यता का व्यवहार्य रूप देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में विलंब और गैर-निष्पादन के लिए गुंजाइश बहुत कम है। यह इस पीढ़ी की विशेषता है।

इस प्रकार यह उन कारकों का एक समूह है जो हमारे देश सहित अन्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों पर प्रभाव डालती हैं। यह कहना जरूरी नहीं है कि परम्परागत जरूरतें भी यथावत हैं। हम किस तरह इन दोनों को मिलाते हैं, सुरक्षा जरूरतों के प्रति कार्यवाही करते हैं और नीति प्रभाव को तेज करते हैं। मेरे विचार से यह आज की चुनौती है। जिसे सामरिक समुदाय द्वारा हल किया जाना चाहिए।

देवियो और सज्जनो,

व्यवस्थित सोच में कोई कार्य अवधारणात्मक स्पष्टता पर निर्भर करता है। आज हमारा विचाराधीन विषय सुरक्षा नीति और विदेश नीति से संबंधित है। पहली बात यह है कि दोनों पर्यायवाची नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के घरेलू आयाम उतने ही प्रासंगिक हैं जितने बाहरी आयाम। सुरक्षा की अवधारणा ने अपने आप में एक नई गहराई और नया अर्थ प्राप्त किया है, यह अब गैर परम्परागत सुरक्षा को संपुटित करता है और व्यापक मानव सुरक्षा पर केन्द्रित है।

विदेश नीति अपने आप में अभिलाषा सूची के आधार पर शून्य में संचालन नहीं है, इसे उस तरीके से परिणाम हासिल करने चाहिए जिसमें कोई देश विदेशों का अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण (इसकी सुरक्षा जरूरतों सहित) के प्रति कार्यवाही करने के लिए मनाता है और राष्ट्रीय क्षमताओं की दृष्टि से समर्थन ढांचा कार्यान्वित करता है।

II

मैं सुझाव देता हूँ कि कल का भारत जरूरतों और परिदृश्यों के ऐसे समूह की दृष्टि से स्वयं की स्थिति का पता करने का प्रयास करेगा। ऐसा करते हुए यह अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन के 6 दिन बाद 7 सितम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपने अभिभाषण में वर्णित मूल उद्देश्यों पर वापस जाएगा। इसको संक्षेप में पुन: प्रस्तुत किया गया है:

- 'हम यथासंभव राजनीति शक्ति समूहों से अलग रहने का प्रस्ताव करते हैं;'
- 'हमारा विश्वास है कि शांति और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हैं तथा कहीं भी स्वतंत्रता से इंकार करना अन्यत्र स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा और इससे संघर्ष और युद्ध होगा;'
- 'हम विशेषकर उपनिवेशवाद से मुक्ति और स्वतंत्र राष्ट्र और लोगों एवं सभी जातियों के लिए समान अवसरों को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप में मान्यता देने में रूचि रखते हैं।'
- 'हम किसी अन्य पर शासन नहीं चाहते हैं तथा अन्य किन्हीं लोगों पर विशेषाधिकार की स्थिति का दावा नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने लोगों के लिए, जहां भी वे जाएं, समान और सम्मानित व्यवहार का दावा करते हैं और हम उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं कर सकते हैं।'
- भारत प्रगति के मार्ग पर है और पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। हम भारत के लाखों लोगों की सफलता, स्वतंत्रता और भलाई के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय परिदृश्य का कोई समालोचक यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या ये विचारणीय बातें लागू रहेंगी? उत्तर सकारात्मक होगा, जैसे कि समय-समय पर सार्वजनिक व्यक्तियों और सरकार में नेताओं द्वारा अधिकृत घोषणा एवं हाल ही में हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित सम्मेलन से साफ है।

इसलिए मुख्य ध्यान हमारे लोगों की सफलता, स्वतंत्रता और भलाई तथा एक सहयोगात्मक, गैर-अधिपत्य वाली विश्व व्यवस्था पर है। अप्रत्यक्ष तौर पर बदलती स्थितियों में इनकी चुनौतियां हमारी सुरक्षा की चुनौतियां बन जाती हैं।

यदि कोई ऐसी चुनौती है जिसे आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में और इसके संभावित प्रभाव के बारे में उजागर करना चाहता हूं तो यह मुख्य रूप से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों संबंधी राज्य-केंद्रिक बहस है। राष्ट्र को बाहरी हमलों और आंतरिक खतरों से सुरक्षित करने को सुरक्षा के अधिक व्यापक दृष्टिकोण के एक घटक-मानव सुरक्षा के रूप में देखा गया है। इस समग्र परिदृश्य में जहां व्यक्तियों और लोगों की सभी प्रकार की हिंसा, भूख, और बीमारी, प्राकृतिक तथा मानवकृत विनाशों, सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक अस्थिरता से सुरक्षा करना लक्ष्य है।

यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस महत्वपूर्ण है और विदेश नीति संबंधी चुनौतियों को तैयार करना और प्रगति करनी है तो यह बड़ा निश्चित कदम उठाना महत्वपूर्ण है। हमें खुद को यह याद दिलाने की भी जरूरत है कि विदेश नीति बनाने तथा 'अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने' के प्रयास करने, और 'राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य भारत के लोगों के हित में है।'

विशेषकर आर्थिक, सामाजिक और मानवीय आयामों से संबंधित भारतीय यथार्थता की जटिलता घरेलू और विदेशी नीति को जोड़ने वाले माध्यम का कार्य करेगी; यह सुरक्षा परिदृश्य के सभी पहलुओं को प्रतिबंधित करता है। विद्वानों को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययनों को करते हुए इस वास्तविकता की मजबूती और कमजोरी के स्रोतों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

देवियो और सज्जनो,

हम उस युग में रहते हैं जहां केवल निश्चितता ही अनिश्चितता है। हम अपनी सुरक्षा और विदेश नीति के अपने दृष्टिकोण को दुनिया और अपने लोगों को कैसे बताएं? हम विषमताओं और अनिश्चितताओं को सुगठित नीतियों और हमारे विविध राजतंत्र और समाज में समर्थन निर्माण में कैसे संश्लेषित करें? इसके एकमात्र उत्तर के लिए लोगों को चर्चा और बहस के केन्द्र में डालने की जरूरत है। हमारे चारों ओर ऐसे समाज हैं जहां भयानक परिणामों के साथ प्राथमिकताओं को उलटा किया गया था।

एहतियात का शब्द असंबद्ध नहीं होगा। दुनिया को श्वेत और काले की दृष्टि से देखना अज्ञानता है। विश्व शांति और अंतराष्ट्रीय समुदाय का भविष्य अधर में है क्योंकि नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षाएं, हेडली बुल्स के शब्दों में, प्रभुत्व, आधिपत्य या श्रेष्ठता की

भावनाएं, उभरती रहती हैं। तथापि, इस संबंध में आशा है कि अन्ततः विवेक आएगा। भारत द्वारा 1988 में प्रस्ताव किए जाने के लगभग दो दशक बाद अमेरिका में अब परमाणु शस्त्रों के चरणबद्ध तरीके से कमी करने और उन्हें समाप्त करने की बात चल रही है। क्या आई डी एस ए के कुछ शोधकर्ता भारतीय परिदृश्य में इन विकल्पों पर खोज करना चाहेंगे।

देवियो और सज्जनो,

हमारी सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चुनौतियों के प्रति एकमात्र दृष्टिकोण वृद्धिशील सफलता है। यह एक दुरूह कार्य है जिसके लिए धैर्य और स्पष्ट उद्देश्य की जरूरत होती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई डी एस ए नए ज्ञान और विचारों का सृजन कर, समाज संबंधी प्रयोजनों पर अधिक ध्यान देकर, और आने वाले वर्षों में हमें पेश आने वाली चुनौतियों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया को रूप देकर इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा।

मैं इस संस्थान को इसके कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद।